उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 4 | 16-28 फरवरी 2026 | ₹ 20/-

अली खामेनेई ने इस्लाम के लिए शहादत दी : उर्दू प्रेस

- ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के खिलाफ भारत में प्रदर्शन
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ा
- अमेरिकी राजदूत द्वारा ग्रेटर इजरायल का समर्थन
- लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के खिलाफ भारत में प्रदर्शन 04
प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा 06
भोजशाला में मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने की पुष्टि 09
लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ 11
महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण रद्द 12

विश्व

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ा 15
अफगानिस्तान में महिला विरोधी कानून 17
पाकिस्तान में गरीबी में भारी वृद्धि 18
बांग्लादेशी सेना में भारी फेरबदल 19
ब्रिटेन की मस्जिद से एक सशस्त्र आतंकवादी गिरफ्तार 21

पश्चिम एशिया

अली खामेनेई ने इस्लाम के लिए शहादत दीः उर्दू प्रेस 22
ट्रम्प द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण हेतु सात अरब डॉलर जुटाने की घोषणा 28
ग्रेटर इजरायल का समर्थन करने पर अमेरिकी राजदूत का विरोध 29
ट्रम्प पर नूरी अल-मलिकी का पलटवार 31
सऊदी अरब की यमन में शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना 33

सारांश

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले से पश्चिम एशिया में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। मृतकों में खामेनेई के परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल समेत सात अरब देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है। इस घटनाक्रम से वहदत-ए-इस्लाम (इस्लामी एकता) के बहुचर्चित प्रचार की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि किसी भी अरब देश ने ईरान का साथ नहीं दिया है। रूस और चीन की सहानुभूति भी केवल शब्दों तक ही सीमित रही है। अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने खुलासा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लगभग तय हो गया था, लेकिन सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें पलीता लगा दिया।

खामेनेई की मौत पर भारत के मुसलमानों में भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए हैं। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से शिया समुदाय के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जबकि सुन्नी समुदाय इन प्रदर्शनों से काफी हद तक अलग रहा। भारत सरकार को खुफिया सूत्रों से यह सूचना मिली थी कि इस घटना का लाभ उठाकर कुछ कट्टरपंथी तत्व देश में अशांति फैला सकते हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ईरान समर्थक कट्टरपंथी प्रचारकों और संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें ताकि वे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान न पहुंचा सकें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उनकी दूसरी इजरायल यात्रा थी। मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारत और इजरायल के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। दोनों देशों ने निवेश, संस्कृति, विज्ञान, मत्स्य पालन और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 27 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उर्दू मीडिया ने नरेन्द्र मोदी के इजरायल दौरे की कड़ी आलोचना की है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध छिड़ चुका है। इस भीषण संघर्ष में अब तक दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक और लड़ाके मारे जा चुके हैं। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए काबुल और कंधार समेत कई प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उसने इन हमलों में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि, वैश्विक मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि पाकिस्तान के इन हमलों में मरने वालों में अधिकांश आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 300 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया है। भारत ने भी अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों की निंदा की है।

ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के खिलाफ भारत में प्रदर्शन

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए हैं। इसके खिलाफ भारत के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई हैं। इन झड़पों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में इन प्रदर्शनों पर रोक भी लगाई गई है।

अवधनामा (2 मार्च) के अनुसार अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में दुख की लहर दौड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह से ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ के छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला। खामेनेई के निधन पर राज्य के शिया नेताओं ने तीन दिवसीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के सभी इमामबाड़ों को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

एतेमाद (2 मार्च) के अनुसार खामेनेई की हत्या के खिलाफ कश्मीर घाटी में दर्जनों स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने खामेनेई की हत्या की निंदा करते हुए मुसलमानों से राज्यव्यापी हड़ताल रखने की अपील की है। उनकी इस घोषणा के बाद घाटी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तीन दिवसीय हड़ताल रहा। श्रीनगर के लाल चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। इन झड़पों में कुछ पुलिसकर्मी सहित कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इसके बाद कश्मीर घाटी के अधिकांश इलाकों में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने कांटेदार तारों से लाल चौक को बंद कर दिया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कश्मीर घाटी में 75 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। इसके

बाद बेमिना, बडगाम और पट्टन समेत कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। लद्दाख में भी 12 स्थानों पर उग्र प्रदर्शन किए गए हैं।

कौमी तंजीम (2 मार्च) के अनुसार खामेनेई की हत्या के खिलाफ पटना, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर और हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दिल्ली में कम-से-कम एक दर्जन स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में शियाओं और वामपंथी दलों ने हिस्सा लिया। कोलाकाता में भी उग्र प्रदर्शन होने की खबर है।

अखबार-ए-मशरिक (2 मार्च) के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी उग्र प्रदर्शन हुए हैं।

एतेमाद (3 मार्च) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए भारतीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे ईरान समर्थक कट्टरपंथी प्रचारकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ये लोग ईरान पर हुए अमेरिकी-इजरायली हमले के विरोध में देश में हिंसा की ज्वाला भड़का सकते हैं। सरकार ने अमेरिकी-इजरायली दूतावासों, यहूदी संस्थानों और अमेरिकी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध करने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है।

एतेमाद (4 मार्च) के अनुसार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी की आलोचना की है। वहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार का वर्तमान रुख अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण जैसा है।

हिंदुस्तान (5 मार्च) के अनुसार जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों पर भारत सरकार की चुप्पी पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। मुफ्ती ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें भी जलाई। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अरब देश अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं और उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार पर चुप्पी साध रखी है।

एतेमाद (4 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की परंपरागत विदेश नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है। यह न सिर्फ नैतिक रूप से, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी खतरनाक है। ईरान और भारत के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ईरान ने कई नाजुक मौकों पर भारत का साथ दिया है। इनमें कश्मीर का मामला भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ईरान भारत को सस्ता तेल भी देता रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया इजरायल दौरे के दौरान इजरायल को 'फादरलैंड' बताया था, जो घोर निंदनीय है। खामेनेई की मौत पर शोक प्रकट न करने का फैसला अनैतिक है। यही कारण है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार की बदलती विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि वह अमेरिका की गुंडागर्दी को बेबसी से देख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा

उर्दू टाइम्स (26 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंच गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। नेतन्याहू ने निर्धारित प्रोटोकॉल तोड़कर अपने मित्र मोदी को गले लगाया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी इजरायल यात्रा थी।

हिंदुस्तान (27 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल ने अपनी साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस दौरान इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में 27 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें निवेश, मत्स्य पालन, संस्कृति, विज्ञान, डोर्नियर विमानों के रखरखाव, सैटेलाइट डेटा, कृषि और अत्याधुनिक तकनीक आदि शामिल हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (27 फरवरी) के अनुसार नरेन्द्र मोदी इजरायली संसद 'नेसेट' को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस दौरान इजरायली संसद के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच न केवल प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं, बल्कि आज एक सुदृढ़ और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी भी है। उन्होंने तकनीक, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में

दोनों देशों के संबंधों पर प्रकाश डाला। मोदी ने कहा कि इजरायल में भारतीय समुदाय और भारत में यहूदी समुदाय ने दोनों देशों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। इजरायली अखबार 'द जेरूसलम पोस्ट' ने मोदी के इजरायल आगमन पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया है। इस अंक के मुख्य पृष्ठ का शीर्षक है, "वेलकम मोदी, नमस्ते, दो प्राचीन देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत।" इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर भी प्रकाशित की गई है।

एतेमाद (26 फरवरी) के अनुसार भारत ने गाजा में स्थाई शांति के प्रयासों का समर्थन किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इजरायली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की तुलना 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से की है। मोदी ने कहा कि हम आपका दर्द महसूस करते हैं। हम आपका दुख बांटते हैं। भारत हमेशा इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले को बर्बर आतंकवादी हमला करार दिया और निर्दोष पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। मोदी ने कहा कि इजरायल से भारत का रिश्ता खून और कुर्बानी से जुड़ा है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इस क्षेत्र में चार हजार से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। सितंबर 1918 में हाइफा में घुड़सवार सेना का हमला सैन्य इतिहास का एक अहम हिस्सा है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे की आलोचना करते हुए कहा है कि गाजा में हुए नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी का इजरायल दौरा और नेतन्याहू को गले लगाना एक युद्ध अपराधी का समर्थन करने जैसा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के इजरायल दौरे की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत ने 29 नवंबर 1981 को फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इसके बाद 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन को विधिवत मान्यता दी गई थी।

अखबार-ए-मशरिक (28 फरवरी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इजरायल को 'फादरलैंड' कहना एक ऐसा जुमला है, जिससे भारतीयों के दिमाग में कई सवाल पैदा हो गए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह शब्द

क्यों इस्तेमाल किया इसकी व्याख्या तो वही कर सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक मान्यता दी थी। अजीब बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन को भी इस घटना के साथ जोड़ दिया। अपने भाषण के दौरान मोदी ने 'हनुक्का' और 'दिवाली' के बीच गहरी सांस्कृतिक समानताओं का भी उल्लेख किया है। मोदी ने हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों के प्रति तो संवेदना व्यक्त की, लेकिन इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर एक शब्द भी नहीं कहा।

मुंसिफ (27 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भारत ने फिलिस्तीन समर्थक अपनी पुरानी नीति की धज्जियां उड़ा दी है। समूचे गाजा को खंडहर में बदलने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहते हैं तो हमारे दिमाग में 2002 में गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों की याद ताजा हो जाती है। भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थाई समिति के कुछ सदस्यों की आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल चले गए। हालांकि, पश्चिम एशिया में विस्फोट स्थिति के कारण कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष इजरायल की यात्रा करना पसंद नहीं करता। क्या विपक्ष के इस आरोप में दम नहीं है कि मोदी अमेरिका और इजरायल के रोबोट बन चुके हैं? उनका हर कदम अमेरिका को खुश करने के लिए ही उठता है। समाचारपत्र ने कहा है कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन को अरबों का क्षेत्र बताया था और इजरायल की स्थापना का विरोध किया था, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था और इजरायल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का भी विरोध किया था।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारत ने 1992 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल ने हमारी सहायता भी की थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इजरायल से बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री की खरीद शुरू की। हालांकि, भारत आधिकारिक तौर पर दो राष्ट्र का समर्थन करता रहा है, लेकिन गाजा युद्ध के दौरान युद्धविराम का समर्थन न करने के कारण मोदी सरकार की दोगली नीति बेनकाब हो गई है। अब मोदी ने इजरायल की यात्रा करके यह साबित कर दिया है कि वे फिलिस्तीन और अरब विरोधी हैं।

एतेमाद (26 फरवरी) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत इजरायल द्वारा प्रस्तावित छह देशों के गठबंधन में शामिल होना चाहता है। यह गठबंधन अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है। सरकार इजरायल से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इजरायली हथियारों के आयात के मामलों में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। सबसे खास बात यह है कि विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर फिलिस्तीन समर्थक नीति का अनुसरण करने का दबाव नहीं डाला। भारत की राजनीति तेजी से

दक्षिणपंथी हो रही है। देश में व्याप्त धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण जनता का एक बड़ा हिस्सा अब फिलिस्तीन संकट को इजरायल के दृष्टिकोण से देखने लगा है। इससे देश के एक वर्ग में यह भावना पैदा हो रही है कि हिंदू और यहूदी मिलकर इस्लाम का नामोनिशान मिटाने के लिए काम कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले जब कोई भी भारतीय नेता इजरायल जाता था तो वह फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों से भी मिलता था। हालांकि, मोदी अपनी इजरायल यात्रा के दौरान न तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में गए और न ही उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का लक्ष्य इजरायल से हथियार खरीदना है। अगर भारत इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात के गठबंधन का हिस्सा बनता है तो यह अमेरिका और इजरायल के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी।

भोजशाला में मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने की पुष्टि

अखबार-ए-मशरिक (25 फरवरी) के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। यह सर्वे रिपोर्ट 2189 पृष्ठों की है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि भोजशाला परिसर में कमाल मौला मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़ कर किया गया था। सर्वे के मुताबिक भोजशाला परिसर में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह, सिक्के, मूर्तियां नक्काशीदार स्तंभ, कमल की आकृतियां और संस्कृत शिलालेख मिले हैं। अदालत ने इस मामले के सभी मुख्य पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि सौंपने का आदेश दिया है और उनसे दो सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई ने 22 मार्च 2024 में लगभग 100 दिनों तक भोजशाला परिसर और उसकी 50 मीटर की परिधि में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और सीमित उत्खन्न किया था। इस टीम में पुरातत्वविद्, अभिलेखविद् और रासायनविद् सहित कई अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस परिसर से 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के शिलालेखों के प्रमाण मिले हैं। इनमें संस्कृत, प्राकृत, नागरी, अरबी और फारसी के शिलालेख शामिल हैं। कुछ शिलालेखों से धार्मिक गतिविधियों का संकेत मिलता है तो कुछ से शिक्षण केंद्र होने का पता चलता है। भोजशाला परिसर में 'पारिजातमंजरी नाटिका' और 'अवनि कूर्मशतकम' जैसे ग्रंथों के शिलालेख भी मिले हैं। इन ग्रंथों का जिक्र एएसआई की पुस्तकों 'एपिग्राफिया इंडिका' और 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम' में भी है। इन शिलालेखों के अनुसार पारिजातमंजरी नाटिका को परमार वंश के राजा अर्जुनवर्मन के गुरु मदन ने लिखा था। इस नाटक का पहला मंचन देवी सरस्वती के मंदिर में हुआ था।

एक शिलालेख में प्राकृत भाषा के दो काव्य मिले हैं। इनमें से एक काव्य 'अवनि कूर्मशतकम' की रचना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। जांच के दौरान 13वीं शताब्दी के लगभग 50 शिलालेखों के टुकड़े मिले हैं। कई पत्थर की पट्टिकाओं की लिखावट को जानबूझकर मिटाया गया था और बाद में इन्हें मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। एक शिलालेख में मुस्लिम सुल्तान महमूद शाह प्रथम का उल्लेख है। इसमें दरगाह और कुएं के निर्माण का विवरण मिलता है। एक तुगलककालीन शिलालेख भी मिला है। इसमें पुरानी मस्जिदों के पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त कमाल मौला की चार कब्रों पर कुरान की आयतें लिखी पाई गई हैं।

उल्लेखनीय है कि 1902 में भोजशाला परिसर के संरक्षण की योजना बनी थी। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। 1972-73 में इस परिसर में हुई खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे।

एएसआई की रिपोर्ट के अुनसार 1034 ईस्वी में परमार वंश के राजा भोज ने ज्ञान की साधना और देवी सरस्वती की अराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया था। यह नालंदा और तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर भोजशाला समेत कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त किया गया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला स्थित मंदिर को नष्ट कर दिया। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहां पर कमाल मौला मस्जिद और दरगाह का निर्माण करवाया।

रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुरातत्व विशेषज्ञ माइकल विलिस ने अपने शोध पत्र में पुष्टि की है कि भोजशाला का निर्माण परमार वंश के महाराजा भोज ने करवाया था। उन्होंने इस परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। उन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि इस मस्जिद के स्तंभ किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं। इस मस्जिद के फर्श पर छह संस्कृत शिलालेख भी मौजूद हैं, जो दसवीं शताब्दी के बताए जाते हैं। इतिहासकार ओसी गांगुली ने 1943 में ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद परमारकालीन वाग्देवी की प्रतिमा पर अपना महत्त्वपूर्ण शोध

प्रकाशित किया था। इस शोध में उन्होंने दावा किया था कि इस प्रतिमा में एक संस्कृत भाषा का शिलालेख मौजूद है। इस प्रतिमा का निर्माण महाराजा भोज ने करवाया था और इसे सरस्वती मंदिर में स्थापित किया था।

एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को हर मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति है। तब से यह सिलसिला जारी है।

लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण देशभर में खून की होली खेलने के इस्लामिक आतंकवादियों के मंसूबे विफल हो गए हैं। सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की कार्रवाई में देशभर से दो दर्जन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह देशभर में आतंकवादी हमलों की तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता और तमिलनाडु में छापे मारकर आठ इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सात बांग्लादेशी हैं। इस आतंकी मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन है। वह पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण ले चुका है और फिलहाल बांग्लादेश में बैठकर इस नेटवर्क का संचालन कर रहा है। यह गिरोह कई राज्यों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीरियल बम धमाके करने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के मोबाइल से कई सनसनीखेज वीडियो भी मिले हैं।

पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने शब्बीर अमहद लोन के निर्देश पर दिल्ली और कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों पर आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले पोस्टर लगाए थे। अतिरिक्ति पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस

गिरोह ने 7 फरवरी को दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। इसके बाद ये लोग कोलकाता भाग गए। कोलकाता पुलिस की मदद से उमर फारूक और रोबिउल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। कुशवाहा ने कहा कि शब्बीर अहमद लोन इस गिरोह को विस्फोटक पदार्थ और हथियार सप्लाई करने वाला था। इन आतंकवादियों से पूछताछ के बाद इस गिरोह से जुड़े छह अन्य आरोपियों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन को 2007 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। वह 2019 में दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। इसके बाद वह फरार होकर बांग्लादेश चला गया था। शब्बीर अहमद जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके सहायक जकीउर रहमान लखवी का करीबी था।

उर्दू टाइम्स (23 फरवरी) के अनुसार दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल बताए जा रहे हैं। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के समर्थन में सामग्री प्रसारित कर रहे थे और भारत में बिना वैद्य दस्तावेजों के रह रहे थे।

चट्टान (23 फरवरी) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी और घन ` जंगलों वाले इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर सैफुल्लाह समेत तीन आतंकवादी मारे गए हैं। इनके कब्जे से दो एके-47 राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस सफल ऑपरेशन के लिए जवानों के साहस और कार्यशैली की प्रशंसा की है।

उर्दू टाइम्स (16 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने यवतमाल और अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिलों में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। इन छापों के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है।

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण रद्द

औरंगाबाद टाइम्स (19 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। सरकारी अध्यादेश के अनुसार 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के संबंध में जो अध्यादेश जारी किया था उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधानसभा से पारित नहीं करवाया जा सका था।

अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा-शिवसेना की सरकार बनी। नई सरकार ने मुसलमानों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया।

गौरतलब है कि राज्य की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने वर्ष 2008 से 2013 के बीच मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुसलमानों के कुछ वर्ग पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने की अनुमति दे दी, जबकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी गई।

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला मुस्लिम विरोधी मानसिकता से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों को सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया गया था, न कि धार्मिक आधार पर। आजमी ने कहा कि जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति और महमूदुर रहमान समिति मुसलमानों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी हैं। भाजपा ने अपनी मुस्लिम विरोधी नीति के कारण मराठा आरक्षण पर तो अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब इसे आधिकारिक तौर पर रद्द भी कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मुस्लिम हमदर्दी भी सिर्फ एक राजनीतिक दांव था। जब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया था तो तो कांग्रेस ने इसे कानूनी रूप देने हेतु कोई कदम क्यों नहीं उठाया?

कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कहा है कि सरकार मुसलमानों को जानबूझकर पिछड़ा रखना चाहती है। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि

मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को जारी रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार ने अदालत के इस निर्देश का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों के कल्याण हेतु जो योजनाएं शुरू की थीं उन्हें भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है।

हिंदुस्तान (23 फरवरी) ने शिकायत की है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुस्लिम विरोधी है। समाचारपत्र ने लिखा है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की पहचान मिटाने और इस्लाम को निशाना बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के राज में मुसलमान, मदरसे, कब्रें, मस्जिदें और दरगाहें सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है। भाजपा की यह नीति संविधान के सरासर खिलाफ है। इससे समाज में विघटन का खतरा बढ़ रहा है, जो देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

कौमी तंजीम (21 फरवरी) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मुस्लिम विरोधी नीति के कारण मुसलमानों का पांच प्रतिशत आरक्षण हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि सत्ता में आते ही भाजपा पहली कुल्हाड़ी मुसलमानों पर चलाती है। यही कारण है कि भाजपा ने मुसलमानों के विकास के लिए यूपीए सरकार द्वारा गठित कई संस्थानों को खत्म कर दिया है, जिनमें मौलाना आजाद फाउंडेशन प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हर साल मुसलमानों के उत्थान हेतु निर्धारित बजट में भी भारी कटौती की जा रही है। भाजपा की यह नीति देश हित में नहीं है।

विश्व

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ा

पिछले कई महीनो से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव ने अब भीषण रूप ले लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान हवाई सीमा का उल्लंघन कर वहां के चार प्रमुख शहरों पर भीषण बमबारी की है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसके हमलों में 500 से अधिक तालिबान लड़ाके और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादी मारे गए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 300 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है।

हिंदुस्तान (28 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पक्तिया प्रांत पर हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले में किसी भी अफगान नागरिक की मौत नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हालिया हमलों में 133 अफगान सैनिक मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना ने 27 अफगान सैन्य चौकियों, दो कोर मुख्यालय और 80 से अधिक टैंक व बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (28 फरवरी) के अनुसार अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित फैजाबाद सैन्य छावनी को अपना निशाना बनाया है। इसके अतिरिक्त नौशेरा, जमरोद और एबटाबाद स्थित सैन्य छावनियों को भी निशाना बनाया है। 'टोलो न्यूज' के मुताबिक

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। भारत ने भी पाकिस्तानी हमलों की निंदा की है और अफगानिस्तान का समर्थन किया है।

अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान सेना ने विमानभेदी तोपों से एक पाकिस्तानी सैन्य विमान को मार गिराया है। यह विमान चीन का बना हुआ था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य अफगानिस्तान में स्थित आतंकवादी अड्डों और उनके समर्थक अफगान सैनिकों को निशाना बनाना है।

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि अफगान सैनिक आतंकवादियों के साथ मिलकर रमजान के महीने में हमारी मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। कतर ने इन दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध पर चिंता प्रकट की है। कतर ने कहा है कि हम इन दोनों देशों के बीच वार्ता के पक्ष में हैं। कतर के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि दो मुस्लिम देशों द्वारा रमजान के महीने में मुसलमानों का खून बहाना बेहद निंदनीय है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी दोनों देशों से अपील की है कि वे धैर्य व शांति से काम लें और एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद कर दें, क्योंकि यह इस्लाम की एकता के हित में नहीं है।

एतेमाद (28 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि अफगान सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 53 स्थानों पर हमले किए थे। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों को विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 274 अफगान सैनिकों की हत्या कर दी है, जबकि 400 से अधिक अफगान सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी वायु सेना ने काबुल स्थित इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाया है। कांधार में भी एक ब्रिगेड मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि हमारी सेना अफगानिस्तान को तबाह करने की पूरी क्षमता रखती है, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान शांति और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल, खैबर, मोहमंद, कुर्रम और बाजौर क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैन्य छावनियों पर हमले किए थे, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की है।

अवधनामा (28 फरवरी) के अनुसार अफगान सरकार ने सभी कबीलाई नेताओं की एक

आपातकालीन बैठक बुलाकर पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा की है। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि अफगान जनता एकजुट होकर पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट हैं। पाकिस्तान हमारे नागरिकों पर बमबारी करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में पूर्व अफगान राजदूत मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ ने कहा है कि पाकिस्तानी उलेमा को अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह रमजान के महीने में मुसलमानों का खून बहाने से बाज आए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने दावा किया कि चीन यह प्रयास कर रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध को रोका जाए। चीन के अतिरिक्त रूस और ईरान ने भी इन झड़पों पर चिंता प्रकट की है और दोनों देशों से अनुरोध किया है कि वे फौरन एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध रोक दें।

कौमी तंजीम (28 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि तालिबान सेना ने पाकिस्तानी सीमावर्ती चौकियों पर हेलीकॉप्टरों से हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना के तोपखानों ने इन हमलों का जवाब दिया, जिसके बाद अफगान सैनिक पीछे हटकर अपनी सीमा में चले गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनका पीछा भी किया।

चट्टान (23 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना के हमले में मारे गए 40 नागरिकों के शवों को दफना दिया गया है। मृतकों में 18 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं।

अफगानिस्तान में महिला विरोधी कानून

उर्दू टाइम्स (20 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं से संबंधित एक नया कानून लागू करने की घोषणा की है। तालिबान सरकार का यह नया कानून पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करने की अनुमति देता है। हालांकि, इसमें शर्त रखी गई है कि इससे उनकी हड्डियां न टूटें या शरीर पर कोई बाहरी घाव न हो। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा जारी एक फरमान में कहा गया है कि महिलाओं को दंडित करने की यह व्यवस्था इस्लामी शरिया के अनुरूप है। नए कानून के अनुसार अगर शारीरिक दंड के दौरान महिला

की कोई हड्डी टूटती है या घाव से खून निकलता है तो पीड़ित महिला काजी की अदालत में शिकायत कर सकती है। अगर यह शिकायत

सही पाई गई तो पति को 15 दिन की जेल हो सकती है।

इसके अतिरिक्त तालिबान सरकार ने एक अन्य फरमान भी जारी किया है, जिसके अनुसार अफगान नागरिकों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए एक ही अपराध हेतु अलग-अलग सजा की व्यवस्था की गई है। पहली श्रेणी में इस्लामिक धार्मिक विद्वान (उलेमा) शामिल हैं। अगर कोई इस्लामिक धार्मिक विद्वान अपराध करता है तो उसे सिर्फ परामर्श दिया जा सकता है। अभिजात वर्ग (अशरफ) से संबंधित अपराधियों को अदालत में बुलाकर परामर्श दिया जा सकता है। मध्यम वर्ग को शारीरिक दंड से मुक्त रखा गया है, लेकिन उन्हें जेल की सजा दी जा सकती है। वहीं, निम्न वर्ग के लोगों को शारीरिक दंड के साथ-साथ जेल की सजा भी दी जा सकती है। गंभीर अपराधों के लिए शारीरिक सजा का निर्धारण इस्लामिक विद्वान करेंगे। अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर जाती है तो उसे जेल की सजा होगी। तालिबान सरकार का यह नया कानून 2009 के 'महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन' कानून को रद्द करके लागू किया गया है, जिसे पूर्ववर्ती अमेरिका-समर्थित सरकार ने पारित किया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार तालिबान सरकार ने देश के नाइयों को यह निर्देश दिया है कि वे लोगों के सिर के बाल और दाढ़ी इस्लामी शरिया के अनुरूप ही काटें। अगर किसी नाई ने किसी भी व्यक्ति के सिर के बाल 'क्रू कट' में काटे या उसकी दाढ़ी पूरी तरह साफ कर दी तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी और उसे तीन महीने की सजा दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि अफगान नागरिक शरिया के अनुरूप आचरण करें और उन्हें पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से बचाया जा सके। ■

पाकिस्तान में गरीबी में भारी वृद्धि

हिंदुस्तान (22 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान में गरीबी की दर पिछले 11 वर्षों के उच्चतम स्तर 29 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि आय की असमानता पिछले 27 वर्षों में सर्वाधिक है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले सात वर्षों में जनता की वास्तविक आय और खपत में भारी कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय पाकिस्तान में लगभग सात करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी न्यूनतम मासिक आय का स्तर अत्यंत चिंताजनक है। यह सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया था। इसके अनुसार 2018-19 के बाद से गरीबी में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2019 में गरीबी दर 21.9 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई। यह 2014 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है।

योजना मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता दी है उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होने और महंगाई दर घटने की संभावना है। सरकार ने आर्थिक असमानता को रोकने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसका प्रभाव

आगामी कुछ वर्षों में नजर आएगा। उन्होंने कहा कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा गरीबी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 11 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई है। पंजाब में गरीबी 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गई है। सिंध में गरीबी दर 24.5 से बढ़कर 32.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गरीबी की दर 28.7 से बढ़कर 35.3 प्रतिशत हो गई है। बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वहां पर लगभग हर दूसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है। बलूचिस्तान में गरीबी की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।

बांग्लादेशी सेना में भारी फेरबदल

उर्दू टाइम्स (28 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी सेना में महत्त्वपूर्ण फेरबदल किए हैं। क्वार्टरमास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को सेना मुख्यालय से हटाकर ढाका के नेशनल डिफेंस कॉलेज का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। फैजुर रहमान को सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान का विरोधी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल डिफेंस कॉलेज के वर्तमान कमांडेंट शाहीनुल हक को सेना मुख्यालय में नियुक्त किया गया है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमांडेंट मेजर जनरल मोहम्मद नसीम परवेज को विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें किसी पश्चिमी देश का राजदूत नियुक्त किए जाने की संभावना है। 19वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) और घाटैल के एरिया कमांडर मेजर जनरल हुसैन अल मोर्शेद को सेना मुख्यालय में नियुक्त किया गया है। वहीं, रंगपुर में तैनात 66वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी और रंगपुर एरिया कमांडर मेजरल जनरल मोहम्मद

कमरुल हसन को ढाका क्षेत्र की कमान सौंपी गई है।

नई सरकार ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग में नियुक्त रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर मोहम्मद हफीजुर रहमान को वापस बुलाकर मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया है और उन्हें एक इन्फैंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मैनुर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (सीजीएस) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम के स्थान पर हुई है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी को सैन्य खुफिया महानिदेशालय (डीजीएफआई) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम के स्थान पर हुई है, जिन्हें विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। मेजर जनरल जेएम इमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर का कमांडेंट नियुक्त किया गया है, जबकि मेजर जनरल फिरदौस हसन को 24वीं इन्फैंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सेना और खुफिया तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। तारिक रहमान चीन और पाकिस्तान से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहते हैं।

हिंदुस्तान (21 फरवरी) के अनुसार तारिक रहमान ने बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे खलीलुर रहमान को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। खलीलुर रहमान को अमेरिका समर्थक माना जाता है। हालांकि, उनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से कभी औपचारिक संबंध नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश सरकार अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता करना चाहती है ताकि उसके कपड़ा उद्योग पर लगे अमेरिकी टैरिफ में राहत मिल सके। हाल ही में अमेरिका ने ब्रेंट क्रिस्टेंसन को बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया है, जो चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अमेरिका का यह प्रयास बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उर्दू टाइम्स (22 फरवरी) के अनुसार बांगलादेश और भारत के बीच संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ गई है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि

पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान शीघ्र ही भारत का दौरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में भाग लिया था और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था।

ब्रिटेन की मस्जिद से एक सशस्त्र आतंकवादी गिरफ्तार

चट्टान (26 फरवरी) के अनुसार पुलिस ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर की एक मस्जिद से एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के पास से एक कुल्हाड़ी और एक चाकू बरामद हुआ है। ब्रिटिश कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर ये दोनों हथियार रखना अवैध है। ब्रिटिश अखबार 'द गार्डियन' के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से कुछ विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तानी मूल का है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह व्यक्ति मैनचेस्टर की सेंट्रल मस्जिद में संदिग्ध तरीके से दाखिल हुआ था। उस समय मस्जिद में लगभग पांच हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो सशस्त्र संदिग्ध मस्जिद में घुसे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा वहां से भागने में सफल रहा।

एक पुलिस अधिकारी साइमन नासिम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका संबंध किस आतंकवादी संगठन से है और वह अवैध हथियारों के साथ मस्जिद में क्यों घुसा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब तक इस व्यक्ति से संबंधित गिरोह के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक उसके बारे में विस्तृत विवरण देना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर 10 स्थानों पर छापे मारकर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। नासिम ने आगे कहा कि पुलिस की सतर्कता के कारण यह संदिग्ध व्यक्ति किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास इस गिरोह के बारे में कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे ताकि आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

अली खामेनेई ने इस्लाम के लिए शहादत दी: उर्दू प्रेस

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और कई शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए हैं।

कौमी तंजीम (2 मार्च) के अनुसार इजरायल और अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में ईरान पर 1200 से अधिक बम गिराए हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और 40 ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए हैं। मृतकों में ईरानी रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादेह और छह अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी हमले के समय खामेनेई के आवास पर एक बैठक में मौजूद थे। खामेनेई की पत्नी, बेटी, दामाद, बहु और पोती की भी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी शामिल हैं।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों 'तसनीम' और 'फार्स' ने इन मौतों की पुष्टि की है। इजरायल और अमेरिका के इस हमले के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और सात दिनों के लिए सभी सरकारी कार्यालय व बाजार बंद कर दिए गए हैं। ईरान में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल की बमबारी में ईरान के 48 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, जबकि ईरानी सेना ने सिर्फ तीन सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। मृतकों में ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुलरहीम मौसवी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी और पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी शामिल हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल समेत आठ अरब देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का मानना था कि अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन उनकी आशाओं पर

पानी फिर गया है। ईरान ने हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसके कारण युद्ध की आग ने कई अरब देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार मरने वालों में ईरानी खुफिया नेटवर्क के प्रमुख सालेह असदी, एसपीएनडी के प्रमुख रजा मोजाफरी और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हुसैन जबल अमेलियन भी शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (1 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन 'शील्ड ऑफ जूडा' के जवाब में ईरान ने 'फतह-ए-खैबर' सैन्य अभियान चलाया। ईरान के मिनाब शहर पर हुए अमेरिका और इजरायल के भीषण हवाई हमले में एक गर्ल्स स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसमें लगभग 180 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिसके कारण हजारों यात्री इन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। ईरान के एक सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कतर के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि ईरान ने दोहा स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया है।

औरंगाबाद टाइम्स (2 मार्च) के अनुसार ईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन को भी अपनी मिसाइल का निशाना बनाया है, जिसके कारण उसे भारी नुकसान पहुंचा है।

अखबार-ए-मशरिक (2 मार्च) के अनुसार रूस ने अयातुल्ला अली खामेनेई को अपने देश में शरण देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि वे आखिरी दम तक दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के मशहद शहर में स्थित इमाम रजा की मजार पर काला झंडा फहराया गया है। ईरानियों ने काले लिबास पहनकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि खामेनेई की हत्या एक गद्दार के कारण हुई है। सीआईए और मोसाद के एजेंट ईरानी खुफिया विभाग में घुसपैठ करने में सफल रहे और उन्होंने इन एजेंसियों को खामेनेई की गुप्त बैठक की सटीक सूचना दी थी। इसी सूचना के आधार पर इजरायल ने हमले का समय बदल दिया और जैसे ही बैठक शुरू हुई उसने मिसाइलों से हमला कर दिया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अफगानिस्तान और इराक के युद्ध के बाद अमेरिक का यह सबसे बड़ा सैन्य अभियान बन सकता है, जो समूचे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। कई यूरोपीय देशों ने अमेरिकी और इजरायली कार्रवाई का समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने अमेरिका और इजरायल की कड़ी आलोचना की है। वहीं, तुर्किये, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की है।

कौमी तंजीम (2 मार्च) ने अपने संपादकीय में खामेनेई को 'इस्लाम का शहीद' बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि खामेनेई ने अमेरिका के सामने झुकने के बजाय शेर की मौत मरना पसंद किया। समाचारपत्र ने लिखा है कि खामेनेई एक प्रभावी वक्ता थे। ईरान के शाह की

खुफिया पुलिस (सावाक) ने उन्हें छह बार गिरफ्तार किया और वे वर्षों तक जेल में रहे। अयातुल्ला अली खामेनेई कभी विदेश नहीं गए। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका समर्थित ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा था। अमेरिका ने खामेनेई की छवि को धूमिल करने के लिए उन्हें एक तानाशाह के रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया है ताकि वह विश्व में एक परमाणु शक्ति के रूप में न उभर सके।

हिंदुस्तान (2 मार्च) ने अपने संपादकीय में खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे इस्लाम के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए शहीद हुए हैं। उनकी मौत के बाद विश्वभर में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका और इजरायल भले ही खामेनेई की मौत से खुश हों, क्योंकि अब इस्लामी जगत में उनका विरोध करने वाला कोई प्रमुख नेता नहीं बचा है, लेकिन खामेनेई ने कभी भी ईरानी हितों से समझौता नहीं किया। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह समझते हैं कि खामेनेई की हत्या के बाद वे ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देंगे तो वे सपना देख रहे हैं। ईरानी उस मिट्टी के नहीं बने हैं, जो किसी जालिम के आगे झुक जाए। समाचारपत्र ने आलोचना की है कि अधिकांश इस्लामी देशों ने ईरान का साथ देने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया है।

हमारा समाज (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि खामेनेई की यह प्रबल इच्छा थी कि वे इस्लाम के लिए शहीद हों और अल्लाह के सामने एक शहीद के रूप में ही हाजिर हों। वे जिस शहादत की कामना करते थे उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है। यही एक मोमिन (सच्चे मुसलमान) की सर्वोच्च शिक्षा होती है कि वह इस्लाम, रसूल और कुरान के लिए अपना बलिदान दे सके। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम दुश्मन देशों का यह प्रयास है कि मुस्लिम देशों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर लड़ाया जाए। उनके आंतरिक मतभेदों और शिया-सुन्नी विवादों को इसलिए उछाला जा रहा है ताकि दुनिया से इस्लाम का नामोनिशान मिटाया जा सके, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के ये नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (4 मार्च) ने अपने संपादकीय में खामेनेई की हत्या की आलोचना की है। समाचारपत्र का कहना है कि कोई भी गैर-इस्लामी देश अपनी ताकत के बल पर किसी इस्लामी देश के शासन में बदलाव नहीं कर

सकता। इराक से लेकर लीबिया तक का इतिहास इस बात का सबूत है कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश के नायक की हत्या किए जाने के बाद भी उन देशों की मुस्लिम जनता ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। जो लोग यह समझते थे कि खामेनेई की हत्या के बाद देश में ऐसा विद्रोह भड़केगा, जो ईरानी शासन को ध्वस्त कर देगा और वहां पर अमेरिका की कठपुतली सरकार स्थापित हो जाएगी, उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ईरान किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह इस्लामी संस्थानों और मुसलमानों की शक्ति का एक सम्मिश्रण है। खुदा ने ईरान का ढांचा इस तरह से बनाया है कि अगर कोई प्रमुख नेता न भी रहे तब भी इस्लामी ढांचा बरकरार रहे। अब ईरान का जो नया नेतृत्व उभरेगा वह इजरायल और अमेरिका के मंसूबों को धूल में मिला देगा। यहूदियों और ईसाइयों के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और ट्रम्प को मुंह की खानी पड़ेगी। खुदा और रसूल ईरान के रक्षक हैं, इसलिए उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

हमारा समाज (2 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि खामेनेई की शहादत अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने लक्ष्यों, विजन और राष्ट्रहित से कभी समझौता नहीं किया। उनकी विदाई भले ही एक गहरा सदमा है, लेकिन एक ऐसा हौसला भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश और इस्लाम के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का संदेश देता रहेगा। शहादत किसी राष्ट्र को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे नया जीवन प्रदान करती है। इस्लाम का इतिहास ऐसे 'मर्द-ए-हक (सत्य के मार्ग पर चलने वाला योद्धा) से भरा हुआ है, जिन्होंने दीन के वर्चस्व के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। खामेनेई की शहादत से इस्लाम को नई ऊर्जा मिलेगी और वह हर दुश्मन का डटकर मुकाबला करेगा।

अवधनामा (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत अमेरिका की तबाही की शुरूआत है। हद तो यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य ईरान के वर्तमान शासन का खात्मा करना है। अर्थात् उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि वे इस्लामी शासन के अंत की आशा रखते हैं। सवाल यह है कि जिस प्रकार ईरान सरकार इजरायल के शासनतंत्र का चयन नहीं कर सकती और यह फैसला सिर्फ इजरायली जनता ही कर सकती है। उसी प्रकार ईरान के लिए कौन सा शासनतंत्र उपयुक्त है इसका फैसला इजरायल और अमेरिका नहीं, बल्कि ईरानी जनता ही करेगी। इतिहास साक्षी है कि आज तक गुंडागर्दी से किसी भी देश का इस्लामी शासन खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह और अधिक मजबूत हुआ है। अमेरिका और इजरायल 1979 के बाद से ही लगातार ईरानी नेताओं और वैज्ञानिकों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि खामेनेई के नेतृत्व में ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया। अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद वहां ऐसी मिसाइलें विकसित की गई हैं, जो ट्रम्प के अनुसार पूरे यूरोप के लिए खतरनाक हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि खामेनेई ने अपनी अंतिम सांस तक

इस्लाम की सेवा की है। यही कारण है कि उनकी मौत के बाद ईरानी जनता ने यह घोषणा की है कि वह उनके बताए रास्तों पर ही चलेगी और अमेरिका व इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देगी। अल्लाह ने कुरान में कहा है, "जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे वे कभी मृत नहीं होंगे, बल्कि वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इससे इस्लाम को नया जीवन मिलता रहेगा।" अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है कि "शहीद की जो मौत है, वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का, वो कौम की जकात है।"

पृष्ठभूमि: ईरान की राजनीति में प्रारंभ से ही ब्रिटेन और अमेरिका का दखल रहा है। 1925 में ईरानी सेना के तत्कालीन सेनापति रजा शाह पहलवी ने काजर राजवंश का तख्ता पलटकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब ईरान के शाह का झुकाव नाजी जर्मनी के हिटलर की तरफ बढ़ने लगा तो ब्रिटेन ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद उनके 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी सौंपी गई। उन दिनों वे स्विट्जरलैंड में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनकी छवि एक दिलफेंक और अय्याश राजकुमार की थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी को हराने के लिए ईरान के तेल संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया। उस समय ईरान के तेल उद्योग का समस्त कार्यभार 'एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी' नामक एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था। ईरान के शाह ने प्रस्ताव दिया कि तेल से होने वाली आय का आधा मुनाफा ईरान को मिले ताकि उस धन का उपयोग देश की समृद्धि के लिए किया जा सके और संभावित राजनीतिक आंदोलनों को रोका जा सके, लेकिन शक्तिशाली एंग्लो-ईरानी कंपनी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

इसके बाद नाराज ईरानवासी एक करिश्माई ईरानी नेता मोहम्मद मोसादेग के पीछे लामबंद हो गए। मोसादेग का संबंध उस परिवार से था, जिसने पहलवी राजवंश के सत्ता में आने से लगभग 200 साल पहले से ईरान पर शासन किया था। 1951 में मोहम्मद मोसादेग ने सत्ता में आते ही वह किया जिसे करने की शाह कभी हिम्मत नहीं करते। मोसादेग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे अपने आर्थिक हितों पर चोट माना। इससे ईरानी जनता में मोसादेग का प्रभाव बढ़ा। मोसादेग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ईरान में सीआईए के एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर ने जनता में उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ प्रेस में भ्रामक खबरें छपवाईं और सड़कों पर प्रदर्शन आयोजित किए। सीआईए ने इन प्रदर्शनों पर अरबों डॉलर खर्च किए। इस साजिश में ईरानी सेना के कुछ उच्चाधिकारियों को भी शामिल किया गया। सीआईए की शह पर ईरानी सैन्य अधिकारियों ने मोसादेग को देशद्रोह के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया।

इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अमेरिका ने इटली में रह रहे मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान

बुलाकर सत्ता फिर से उनके हाथ में दे दी। मोसादेग को तीन साल तक जेल में रखने के बाद उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, जहां 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका का तर्क था कि उसे ईरान के अंदरूनी मामलों में इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा है ताकि रूस ईरानी तेल का लाभ न उठा सके। सत्ता में आते ही शाह ने ईरानी जनता से लंबे-चौड़े दावे किए। शाह ने ईरान में पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा दिया और अपने विरोधियों को सख्ती से कुचला। कहा जाता है कि उन्होंने ईरानी तेल से होने वाली आय को अपनी अय्याशी और विकास की अन्य फर्जी योजनाओं पर दोनों हाथों से लुटाया।

1970 के बाद ईरानी जनता में शाह का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने उन ईरानी मुस्लिम उलेमाओं के खिलाफ सख्ती दिखाई जो ईरान के पश्चिमीकरण का विरोध कर रहे थे। कहा जाता है कि इस विरोध के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी का भी हाथ था। 1979 में जनता के इस विद्रोह ने भीषण रूप धारण कर लिया। पेरिस में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे ईरान के प्रमुख शिया नेता रुहोल्ला खुमैनी 1 फरवरी 1979 को एक विशेष विमान से तेहरान पहुंचे। इसके बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बना दिया गया और उन्होंने कट्टर इस्लामी नियमों के अनुसार ईरान पर शासन करना शुरू कर दिया। खुमैनी ने अमेरिका को 'बड़ा शैतान' कहकर संबोधित किया और इजरायल पर आरोप लगाया कि उसने फिलिस्तीनी भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है।

खुमैनी के कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही उनके समर्थकों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 66 अमेरिकियों को बंदी बना लिया। इस दौरान मोहम्मद रजा पहली अपनी जान बचाकर परिवार सहित अमेरिका भाग गए। कहा जाता है कि अमेरिका के उकसाने पर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध लगभग नौ सालों तक चला। बाद में सद्दाम हुसैन ने रूस का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया तो अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन के शासन का अंत कर दिया।

खुमैनी अब वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने एक अनुयायी मोहम्मद मोंतजरी को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन मतभेदों के कारण उन्हें हटा दिया गया। अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए खुमैनी ने ईरानी संसद की एक विशेष बैठक बुलाई और संविधान में संशोधन करके अयातुल्ला अली खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि 'अयातुल्ला' एक पदवी है, जो शिया धर्मगुरुओं को ईरानी शहर कोम स्थित शिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।

ट्रम्प द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण हेतु सात अरब डॉलर जुटाने की घोषणा

उर्दू टाइम्स (21 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अध्यक्षता में गाजा के पुनर्निर्माण हेतु 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक वाशिंगटन में आयोजित की गई। इस बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ट्रम्प ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य गाजा का पुनर्निर्माण, हमास का नि:शस्त्रीकरण और युद्ध के कारण गाजा की बदहाल अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। नौ देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए सात अरब डॉलर जुटाने पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि अमेरिका पहले ही इस योजना के लिए 10 अरब डॉलर देने की घोषणा कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि इस पूरी योजना पर 70 अरब डॉलर खर्च होने की संभावना है, इसलिए आवश्यक फंड इकट्ठा करने के लिए हमें अभी और भी अधिक प्रयास करने होंगे। खास बात यह है कि इस बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाड़ा समेत कई अन्य देशों ने भाग नहीं लिया। ट्रम्प ने जोर दिया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए यह जरूरी है कि हमास पूर्ण रूप से नि:शस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जाए।

कौमी तंजीम (21 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान ने गाजा में स्थाई शांति की स्थापना हेतु नवगठित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आईएसएफ के अमेरिकी कमांडर मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स ने कहा कि इस शांति सेना में अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और कोसोवो ने अपने सैनिक भेजने पर सहमति प्रकट की है। विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने इस शांति सेना में अपने आठ हजार सैनिक भेजने पर सहमति प्रकट की है। हमास द्वारा गाजा क्षेत्र को खाली करने के बाद वहां शांति और कानून व्यवस्था एक विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। इसमें कुल पांच हजार पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा।

इस बैठक में इजरायल के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक हमास का पूरी तरह से नि:शस्त्रीकरण नहीं हो जाता तब तक गाजा समस्या का कोई स्थाई समाधान संभव नहीं है। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा पुनर्निर्माण कोष में एक-एक अरब डॉलर देने का वायदा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'बोर्ड ऑफ पीस' की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भागीदारी की प्रशंसा की। बैठक में उनका

परिचय कराते हुए ट्रम्प ने कहा कि "मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पसंद हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेरी उनसे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई थी। फील्ड मार्शल एक महान व्यक्तित्व हैं। वहीं, शहबाज शरीफ ने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि मेरे हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम संभव हुआ, जिसमें लगभग 25 मिलियन लोगों की जान बच गई।"

अवधनामा (22 फरवरी) के अनुसार फिलिस्तीनी बोर्ड के अध्यक्ष फरीद अबू महमूद ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प एक तानाशाह शासक हैं, जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने गाजा बोर्ड ऑफ पीस इसलिए बनाया है ताकि फिलिस्तीन पर कब्जा करके उसे इजरायल के हवाले किया जा सके। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (ईसीएफआर) ने कहा है कि बोर्ड की बैठक से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं वे अत्यंत गंभीर हैं और इनसे फिलिस्तीनियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। ईसीएफआर ने आरोप लगाया है कि ट्रम्प ने इस बोर्ड का गठन करके फिलिस्तीनी मुसलमानों की राय को खारिज कर दिया है। वे आर्थिक विकास के नाम पर इस क्षेत्र को हड़पना चाहते हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि इस बैठक में यूरोपीय कमीशन को अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने उसे इसके लिए अधिकृत नहीं किया था।

हिंदुस्तान (19 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि क्या यह बोर्ड गाजा में स्थाई शांति बहाल करने में सफल होगा या फिर यह मामला और उलझ जाएगा? यह समझना कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस के गठन का उद्देश्य सिर्फ गाजा का पुनर्निर्माण करना है, एक बड़ी भूल होगी। इजरायल और अमेरिका का असली निशाना कुछ और ही है। इसी तरह से यूरोप और अरब देशों के भी अपने-अपने निहित स्वार्थ हैं। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बोर्ड की आड़ में गाजा क्षेत्र को हड़पना चाहता है या फिर वह इसे इजरायल को एक तोहफे के रूप में सौंपने की तैयारी कर रहा है? समाचारपत्र ने कहा है कि सबसे जटिल समस्या हमास के नि:शस्त्रीकरण की है। क्या अमेरिका इस प्रस्ताव की आड़ में फिलिस्तीनियों के सशस्त्र संघर्ष का गला घोटना चाहता है? अगर दुनिया गाजा में स्थाई शांति चाहती है तो उसे फिलिस्तीनी जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही इस क्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपनी होगी, अन्यथा यह समस्या और भी जटिल हो जाएगी।

ग्रेटर इजरायल का समर्थन करने पर अमेरिकी राजदूत का विरोध

अवधनामा (22 फरवरी) के अनुसार इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि इजरायल को मध्य-पूर्व की भूमि पर कब्जा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने यह जमीन इजरायलियों को दी है। जब अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने माइक हकाबी से इजरायल की भौगोलिक सीमाओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मध्य-पूर्व का एक बड़ा

हिस्सा इजरायल की सीमाओं के भीतर आता है, क्योंकि बाइबिल में इसकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है। हकाबी ने दावा किया कि ईश्वर ने यह पूरी भूमि अब्राहम के वंशजों को सौंपी थी, इसलिए इजरायल को नील नदी से लेकर फरात नदी तक के क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार है। इसमें इराक में फरात नदी से लेकर मिस्र में नील नदी के बीच का इलाका शामिल है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आज के लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हैं। कार्लसन ने हैरानी प्रकट करते हुए हकाबी से कहा कि इस तरह तो आप ग्रेटर इजरायल की प्रस्तावित योजना का समर्थन कर रहे हैं। इस पर हकाबी ने जवाब दिया कि इजरायल वर्तमान में इस तरह की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि वह उस भूमि की सुरक्षा चाहता है जो वर्तमान में उसके पास है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि वे स्वयं को ईसाई-यहूदी मानते हैं और इजरायल के प्रबल समर्थक हैं।

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई मुस्लिम देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी द्वारा ग्रेटर इजरायल योजना का समर्थन करने की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने हकाबी के इस बयान को बेहद खतरनाक और उत्तेजनात्मक करार दिया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अुनसार माइक हकाबी पहले पादरी थे और वे इजरायल के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। यह बयान संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस पर संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ-साथ इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी), अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद के हस्ताक्षर हैं।

इस बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राजदूत हकाबी का यह बयान अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और गाजा में युद्ध खत्म करने की राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना के बिल्कुल विपरीत है। जॉर्डन के गृह मंत्रालय ने इसे इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता पर हमला करार दिया है, जबकि कुवैत ने कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। ओमान का कहना है कि इस तरह के बयान से इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ गई है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल को गैर-कानूनी कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी क्षेत्रों या किसी भी

अरब देश की भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे इस क्षेत्र में जंग की ज्वाला भड़क सकती है।

अवधनामा (24 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि माइक हकाबी का यह बयान हकीकत से परे है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर अडिग है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हकाबी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वे इजरायल को उन सभी क्षेत्रों (नील से फरात तक) को वापस लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे उस भूमि को लेने की बात अवश्य कर रहे हैं, जिसके इजरायली कानूनी और ऐतिहासिक रूप से मालिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल जॉर्डन, लेबनान, इराक या सीरिया पर कब्जा करने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि वह सिर्फ अपने लोगों की रक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।

ट्रम्प पर नूरी अल–मलिकी का पलटवार

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 फरवरी) के अनुसार इराक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नूरी अल-मलिकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ट्रम्प ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने की सलाह दी थी। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर अल-मलिकी इराक के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका इराक सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा और उसे दी जाने वाली सभी अमेरिकी सहायता बंद कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि नूरी अल-मलिकी पहले भी इराक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी विरोध और भारी दबाव के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नूरी अल-मलिकी को ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों का समर्थक माना जाता है। समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी शासन का तख्तापलट करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी ओर, उनका यह भी प्रयास है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी सरकार न बने जो ईरान का समर्थन करती हो। अमेरिका की यह नीति रही है कि विश्व में ऐसी कोई भी सरकार न हो जो उसके हितों का विरोध

करती हो। यही कारण है कि अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था।

नूरी अल-मलिकी ने स्पष्ट किया है कि वे इस पक्ष में नहीं हैं कि सरकारी सेना के अतिरिक्त कोई भी अन्य संगठन अपने पास हथियार रखे। उनका कहना है कि हथियार सिर्फ सरकारी सेना के पास ही होने चाहिए। यही समस्या इराक के पड़ोसी देश सीरिया में भी है। सीरिया में विद्रोही कुर्दों के पास हथियार हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ने सीरिया के पूर्व शिया शासक बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के लिए कुर्दों को हथियार उपलब्ध कराए थे। बशर अल-असद रूस और ईरान के समर्थक माने जाते थे। दिसंबर 2024 में हुए एक बड़े विद्रोही हमले के बाद उनका तख्तापलट कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें सीरिया छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी।

नूरी अल-मलिकी ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका को इराक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वे ट्रम्प के इशारे पर प्रधानमंत्री पद की दौड़ से पीछे हट जाएं। दुनिया के किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारी जनता को यह आदेश दे कि वे किसे वोट दें। अल-मलिकी ने कहा कि इराक के लिए अमेरिका के साथ संबंध बेहद महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वे हमारे आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी को कूड़ेदान में फेंकता हूं।

नूरी अल-मलिकी इराक के एकलौते ऐसे नेता हैं, जो दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अल-मलिकी 2006-2014 तक ईरान के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान इराकी सरकार के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। सद्दाम हुसैन की हत्या के बाद नूरी अल-मलिकी को सत्ता में लाने हेतु अमेरिका ने विशेष भूमिका निभाई थी। हालांकि, बाद में उन्होंने ईरान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दीं, जो अमेरिका को रास नहीं आया। अमेरिका ने इराक में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं, जिनके कारण अल-मलिकी को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि नूरी अल-मलिकी शिया समुदाय से हैं। इराक की बहुसंख्यक आबादी शिया है, लेकिन सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान देश की सत्ता सुन्नियों के हाथों में थी।

अवधनामा (17 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया की जेलों में बंद इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पांच हजार से अधिक कैदियों को इराक भेजने का फैसला किया है।

अमेरिकी सेना ने यह फैसला सीरिया में स्थाई शांति स्थापित करने और सीरियाई जेलों से इन आतंकवादियों के फरार होने की घटनाओं को रोकने के लिए किया है। इराकी अधिकारियों ने

पुष्टि की है कि सीरिया से कुल 7045 कैदियों को इराक भेजा गया है। इन कैदियों का संबंध दुनिया के 60 विभिन्न देशों से है। इराक के नेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल ज्युडिशियल कोऑपरेशन के अनुसार इन कैदियों में से तीन हजार 543 कैदी सीरियाई मूल के हैं, जबकि 467 इराकी हैं। वहीं, 710 का संबंध अन्य अरब देशों से है। शेष 980 कैदियों का संबंध यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से है। इन कैदियों को सीरिया से इराक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया एक महीने पहले शुरू की गई थी। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। इन खतरनाक आतंकवादियों के खिलाफ इराकी कानून के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे।

गौरतलब है कि आईएसआईएस ने 2014 में इराक और सीरिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और अमेरिका की सहायता से 2017 में इराक और 2018-19 में सीरिया में आईएसआईएस के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। तब से हजारों आतंकवादी कुर्द बलों की निगरानी में सीरिया के उत्तर-पूर्वी और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अस्थाई बंदी शिविरों में रह रहे थे। इन कैदियों के फरार होने का खतरा था, इसलिए अब उन्हें इराक भेज दिया गया है।

सऊदी अरब की यमन में शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना

हिंदुस्तान (26 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने यमन के छह प्रांतों में शिक्षा के प्रसार के लिए एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके प्रथम चरण में लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में सऊदी सरकार के 'सऊदी

विकास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम (एसडीआरपीवाई) और यमन के 'अल-औन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट' ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले चरण में यमन के ग्रामीण इलाकों में छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए 500 स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्कूलों के संचालन के लिए सउदी अरब के सहयोग से प्रशिक्षित यमनी महिलाओं को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि यमन के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच शिक्षा का व्यापक प्रसार हो सके।

योजना के दूसरे चरण में सऊदी अरब में 150 लड़कियों को इन स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षण के लिए सउदी अरब के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यमन में प्रोफेशनल कॉलेजों की भी स्थापना की जा रही है। इनमें ताइज यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, फार्मेसी और नर्सिंग के तीन कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया है। इन कॉलेजों के निर्माण और आधुनिक उपकरणों का पूरा खर्च सऊदी सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त इन कॉलेजों में शिक्षा देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षित सऊदी मूल के प्रोफेसरों को भी भेजा जाएगा।

अदन यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रसायन विज्ञान की 28 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनका पूरा खर्च सऊदी सरकार उठाएगी। यमन में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पहली आपराधिक जांच लैब स्थापित की जा रही है। साथ ही सबा रीजन यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जा रहा है और इन संस्थानों के लिए 200 से अधिक विशेषज्ञों को विदेशों में प्रशिक्षित करने का खर्च भी सऊदी सरकार उठाएगी।

इसके अतिरिक्त हद्रामौत यूनिवर्सिटी और सेयुन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और सूचना तकनीक के दो कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। अल-महरा में अप्लाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज और सोकोट्रा में एक तकनीकी संस्थान व शिक्षा कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यमन के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 268 योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा, परिवहन, कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में यमनी युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

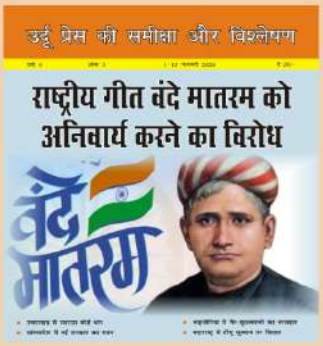

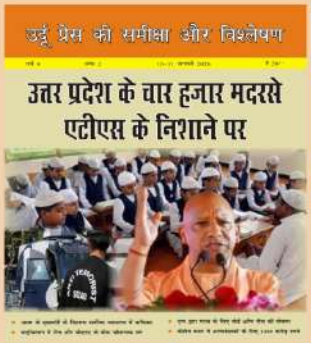

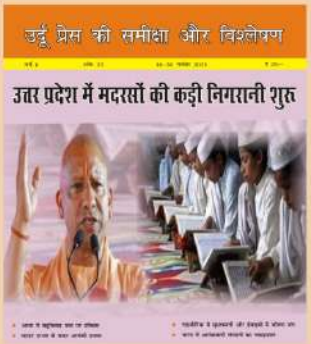

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in